परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू किया गया है। जिसमें निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वयन होंगे:- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-रोजगार कार्यक्रम 4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 8. सूचना संप्रेषण मद	500000	**1.** स्वयं सहायता समूह का गठन-3000 (प्रति समूह 10-15 सदस्य), स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि-4000, एरिया लेवल फेडरेशन का गठन-50, एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ती निधि-200, टाऊन लेवल फेडरेशन का गठन-5, वित्तीय समावेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम-100, शहर आजीविका केन्द्र (सीएलसी)-28 (प्रत्येक शहर स्तर पर 1 सीएलसी) **2.** कौशल उन्नयन हेतु विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण -12000 **3.** व्यक्तिगत ऋण प्रकरण-4400, समूह ऋण-330, स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण -2200 **4.** विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर पर-06/ शहर स्तर पर-75, सामु संगठक-157 **5.** पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे-109, वेण्डरों को परिचय पत्र वितरण-18000, वेंडिग प्लान का चिन्हांकन एवं निर्माण-15, शहरी पथ विक्रेताओं हेतु प्रशिक्षण-6000 **6.** नवीन आश्रय स्थल निर्माण-5, नवीन आश्रय स्थल हेतु सामग्री क्रय-25, आश्रय स्थलों के संचालन रख-रखाव-50	
2	स्मार्ट सिटी	स्मार्ट सिटीमिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देय उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते है, एक स्वच्छ और सुस्थित वातावरण प्रदान करते	3560000		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		है और स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवरंचना घटक निम्नानुसार है:- 1. पर्याप्त जलपूर्ति 2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति 3. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सहित साफ-सफाई 4. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन		1. रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 3123.00 करोड़ का प्लान स्वीकृत है, जिसमें लगभग रू. 470.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए है, राशि रू. 380.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है, राशि रू. 775.00 करोड़ की निविदाएं जारी, राशि रू. 670.00 करोड़ की डीपीआर अनुमोदित एवं राशि रू. 1644.00 करोड़ डीपीआर तैयारी पर है। 2. बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 4053.00 करोड़ के प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। लगभग रू. 43.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए है। राशि रू. 1178.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है एवं शेष परियोजनाएं प्लानिंग एवं स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। 3. अटल नगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के विकास के राशि रू. 1711.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। लगभग राशि रू. 461.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है, राशि रू. 180.00 करोड़ की परियोजनाएं प्लानिंग स्तर पर है।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		5. विशेषत: गरहबों के लिए किफायती आवास 6. सक्षम आई.टी. कनेक्टीविटी और डिजीटेलाईजेशन 7. सुशासन, विशेषत: ई-गवर्नेस ओर नागरिक भागीदारी 8. सुस्थिर पर्यावरण 9. विशेषत: महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा 10. स्वास्थ्य और शिक्षा			
3	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्रीय योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार के स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित 05 घटक में योजना कियान्वयन होंगे:- 1. सार्वजनिक शौचालय 2. निजी/व्यक्तिगत शौचालय 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण 5. कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय कये जाने हेतु	1000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नांकित 05 घटक में योजना का कियान्वयन होगा:- **1.** सार्वजनिक शौचालय **2.** निजी/व्यक्तिगत शौचालय **3.** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन **4.** सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण **5.** कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय	
4	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये कियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण	4565600		

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण		माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पुर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने व्यापक मिशन ''2022 तक सबके लिए आवास'' शुरू किया है । योजनान्तर्गत कियान्वयन अवधि 2015 से 2022 में सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है । प्रधानमंत्री आवास योजना की मिशन अवधि मार्च 2022 तक नियत है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीएलसी घटक अंतर्गत 75000 आवास (प्रगतिरत् एवं अप्रारंभ) तथा एचपी घटक अंतर्गत 50000 आवास (प्रगतिरत् एवं अप्रारंभ) को पूर्ण कराया जाना है।	
5	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए बर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना ।	2200000	राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया ।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
6	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	74100	आदिवासी उपयोजना में-625504 लगभग एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में-812415 लगभग नागरिक लाभान्वित होंगे।	
7	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है ।	40000	165 निकायों में आवश्यकतानुसार वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	
8	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार आदिवासी उपक्षेत्र, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं सामान्य क्षेत्रों के निकायों को पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविघाओं लिए अनुदान	900000	165 नगरीय निकायों के लिए निम्नाकिंत कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. ठोस अवशिष्ट सामग्री क्रय प्रबंधन	
9	विशिष्ट प्रयोजनार्थ	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान निश्चित अनुपात में स्वीकृत किया जाता है ।	2000	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है ।	
10	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाएगें, जिसमें लगभग 4150 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी/कर्मचरियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15000 लाभान्वित होंगे ।	

परिणामी बजट वर्ष 2021-22

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2021-22	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
11	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	4815549	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निम्नानकित कार्य प्रमुखत: से किया जाना है । 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लाई ओव्हर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किग स्थल निर्माण 4. पशु वंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोटर्स काम्पलेक्स	